आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 22.02.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- राज्य विधानसभा के बजट सत्र का आज पांचवा दिन, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कल के विवादित बयान को लेकर सदन में विपक्ष का शोर–शराबा।
- प्रदेश में शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी सेवाओं में अनुकंपा के आधार पर आवेदन करने के लिए 2 साल के बजाय 5 साल का समय मिलेगा।
- विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में स्थानीय युवाओं ने पांच टन कचरा एकत्रित कर ग्रीन औली–क्लीन औली का संदेश दिया।
- पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस प्रदर्शनी में आलू की नवीनतम प्रजातियां रहीं आकर्षण का केंद्र।

<u>बजट सत्र</u>

राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज शनिवार को भी जारी है, जो आमतौर पर कार्यवाही का दिन नहीं होता। इस बीच, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कल के विवादित बयान को लेकर विपक्ष ने शोर–शराबा किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को घेरते हुए बयान पर सफाई मांगी, लेकिन सत्ता पक्ष के किसी मंत्री या विधायक ने प्रेमचंद अग्रवाल का समर्थन नहीं किया। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने उनसे सदन में माफी मांगने की मांग की, जबकि बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने पहाड़ के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए पर्चा फाड़ दिया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण नाराज हो गईं और लखपत बुटोला को सदन से बाहर जाने का निर्देश दिया।

<u>शहीद सैनिक परिवार</u>

प्रदेश सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी सेवाओं में अनुकंपा के आधार पर आवेदन करने के लिए 2 साल के बजाय 5 साल का समय मिलेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गत 19 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट से इस फैसले को मंजूरी मिलने के बाद यह नियम लागू कर दिया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि राज्य सरकार की इस नीति के तहत अब तक 27 शहीद सैनिकों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। नई व्यवस्था से भविष्य में और अधिक परिवारों को राहत मिलेगी और वे सरकारी सेवाओं में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह फैसला शहीदों के परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से न केवल परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि उन्हें समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्राप्त होगा।

मसूरी मॉक ड्रिल

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा देश भर में रोपवे प्रोजेक्ट के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में मसूरी के भट्टा फॉल रोपवे में संयुक्त मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान रोपवे में फंसे पांच लोगों को रस्सी के सहारे पहाड़ी पर उतारा गया। मॉक ड्रिल में स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, मसूरी पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और फायर सर्विस के जवानों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। अधिकारियों ने बताया कि भट्टा फॉल रोपवे की मॉक ड्रिल एक महत्वपूर्ण सुरक्षा अभ्यास रहा। इसका उद्देश्य रोपवे के कर्मचारियों, बचाव दल और स्थानीय अधिकारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित और सही कदम उठाने की ट्रेनिंग देना है।

फ्रीज जोन

रुद्रप्रयाग जिले में ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन परियोजना के तहत निर्माणाधीन तिलणी और घोलतीर रेलवे स्टेशन के आसपास 400 मीटर के क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित किया गया है। अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे स्टेशन परिसरों के 400 मीटर के दायरे को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि शासन ने निर्देश दिए हैं कि रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तिलणी और घोलतीर में सीमांकन कार्य पूरा किया जाए। साथ ही प्रशासन को सीमांकन कार्यवाही की जानकारी देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

क्लीन औली संदेश

चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बीच स्थानीय युवाओं और स्कीयरों ने प्लास्टिक उन्मूलन अभियान के तहत पांच टन कचरा एकत्रित कर पर्यटकों को ग्रीन औली–क्लीन औली का संदेश दिया। पर्यावरण संरक्षण और संवर्द्धन के लिए समर्पित स्थानीय युवाओं की ईको फ्रेंडली ग्रीन ट्रेल टीम ने प्लास्टिक उन्मूलन अभियान चलाया। टीम के प्रभारी दिनेश भट्ट ने बताया कि पर्यटक यहां प्लास्टिक का कचरा छोड़ जाते हैं, इसलिए उन्हें जागरूक करने का संदेश दिया जा रहा है।

पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय युवा राहुल ने कहा कि औली को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रखने का संकल्प लिया गया है। पर्यटकों को भी यहां की सुंदरता और स्वच्छता को बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए।

वहीं, जिला पर्यटन अधिकारी बृजेश पांडे ने बताया कि गत दो महीने के दौरान औली में 70 हजार से अधिक पर्यटक आए हैं, इससे कारोबारियो को अच्छा लाभ पहुंचा है।

कृषि विज्ञान प्रदर्शनी

गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस प्रदर्शनी में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित कुफरी चिप्सोना–5, कुफरी भास्कर और कुफरी जमुनिया प्रजातियां आकर्षण का मुख्य केंद्र रहीं। संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. आर.के. सिंह ने बताया कि संस्थान द्वारा विकसित तीनों प्रजातियों को प्रधानमंत्री ने किसानों को समर्पित किया।

केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, मोदीपुरम के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. सतीश कुमार लूथरा ने बताया कि अभी तक संस्थान ने 76 प्रजातियां विकसित की हैं, जिनमें अधिक उपज देने वाली, अधिक तापमान सहने वाली और मानव स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद प्रजातियां हैं। उन्होंने बताया कि कुफरी जामुनिया प्रजाति एक बैंगनी–मांस वाला आलू है, जो एंथोसायनिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है।

कारण बताओ नोटिस

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हल्द्वानी–काठगोदाम नगर निगम को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 के तहत लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने इस संबंध में नगर आयुक्त को 30 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि नगर निगम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का पालन करने में विफल रहा है। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए, बोर्ड ने नगर निगम पर 1 अप्रैल 2020 से प्रति माह एक लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने की चेतावनी दी है। बोर्ड ने ठोस अपशिष्ट के सही ढंग से निस्तारण न होने, वायु गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन और कचरे के ढेर जमा होने को लेकर चिंता जताई है।

बैठक चमोली

चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिला योजना के तहत प्रस्तावित जल संस्थान और पेयजल निगम के कार्यों की समीक्षा। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी चार धाम यात्रा और ग्रीष्मकाल में होने वाली पेयजल किल्लत से निपटने के लिए भी तैयारियां पूरी करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को नियमित योजनाओं के साथ ही आवश्यकता के अनुरूप दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने की बात कही, जिससे लम्बे समय तक योजना का आमजन को लाभ दिया जा सके।